दैनिक
स्वर्णिम प्रदेश

PRN: MCN/329/2025-2027
epaper.swarnimpradesh.in

संरक्षक: मां वैष्णो देवी

विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें

अगर आप अपने विशेष अवसरों को खास बनाना चाहते हैं या महत्वपूर्ण सूचनाओं को व्यापक जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, तो दैनिक स्वर्णिम प्रदेश आपके लिए सही मंच है। चाहे जन्मदिन की बधाई हो, शादी की सालगिरह, गुमशुदगी की सूचना, कानूनी नोटिस या कोई अन्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक विज्ञापन, हम आपके संदेश को सही तरीके से पहुंचाने में मदद करेंगे। आपके विज्ञापन से समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जो इसे और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी।

ईमेल: swarnimpradesh@yahoo.com
या वाट्सऐप नं. 8898271111

वर्ष : 9 • अंक : 87 • मुंबई, गुरुवार 12 नवंबर, 2026 • पृष्ठ : 6 • मूल्य: 2 रुपये • संपादक : सुनील कुमार तिवारी • Email: swarnimpradesh@yahoo.com www.swarnimpradesh.in

डिगारू में कोलकाता-साइरंग एक्सप्रेस के पांच डिब्बे और इंजन पटरी से उतरे

सभी यात्री सुरक्षित



संवाददाता

गुवाहाटी। असम के डिगारू रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह कोलकाता-साइरंग एक्सप्रेस के पांच डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए। इस घटना में सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। यह जानकारी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने दी।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा के अनुसार, ट्रेन संख्या 13125 कोलकाता-साइरंग एक्सप्रेस बुधवार सुबह करीब 6 बजकर 54 मिनट पर डिगारू रेलवे स्टेशन पहुंच रही थी। गुवाहाटी से करीब 44 किलोमीटर दूर स्थित इस स्टेशन पर दूसरी ट्रेन को प्राथमिकता देने के लिए एक्सप्रेस को रिसीव किया जा रहा था। इसी दौरान लोको पायलट गति को नियंत्रित नहीं कर सके, जिसके कारण इंजन सहित पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना के तुरंत बाद राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। प्रभावित यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक ट्रेन की व्यवस्था की गई है। फंसे हुए यात्रियों की आगे की यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष ट्रेन घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। यात्रियों को पेयजल और खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के महाप्रबंधक सहित वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर बहाली कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। रेलवे ने बताया कि अप लाइन पर रेल परिचालन बहाल कर दिया गया है और अप तथा डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। विभिन्न स्थानों पर रोकी गई ट्रेनों को धीरे-धीरे उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। इस घटना के कारण कुछ स्थानीय ट्रेनों को रद्द या आंशिक रूप से समाप्त किया गया है। ट्रेन संख्या 15769 अलीपुरद्वार जंक्शन-मरियानी जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस को कामाख्या में आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया है, जबकि ट्रेन संख्या 75727/75728 गुवाहाटी-हैबरगांव-गुवाहाटी डीएमयू सेवा रद्द कर दी गई है। यात्रियों और उनके परिजनों की सहायता के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबरः कटिहारः 9002041806, 9002041952, 9771441956 किशनगंजः 06456226794, 06456226795 न्यू जलपाईगुड़ीः 6287699880 गुवाहाटीः 03612731621, 2731622, 2731623 लामडिंगः 03674263858, 265958, 263831 बदरपुरः 03843269546, 269548, 268424, 269547 सिलचरः 03842245414, 245419, 245423। गुवाहाटी के नजदीक डिगारू में कल सुबह कोलकाता-साइरंग एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि बुधवार की सुबह लगभग 06:54 बजे, असम की राजधानी के डिगारू रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 13125 कोलकाता- साइरंग एक्सप्रेस को एक दूसरी ट्रेन को रास्ता देने के लिए रोका जा रहा था। इस दौरान लोको पायलट ट्रेन की गति को नियंत्रित नहीं कर सके, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना में इंजन और 5 कोच पटरी से उतर गए। उन्होंने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए दूसरी ट्रेन की व्यवस्था की गई है। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं और महाप्रबंधक (जनरल मैनेजर) तथा अन्य अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं।

मुंबई एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नवी मुंबई शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर सीएम फडणवीस का विरोध, टर्मिनल-1 के पुनर्विकास का दिया विकल्प

- पहले नया टर्मिनल बनाने का सुझाव, ताकि निर्माण के दौरान प्रभावित न हों उड़ान संचालन
- एयरलाइनों की आपत्तियों के बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का स्थानांतरण मार्च 2027 तक टला



संवाददाता

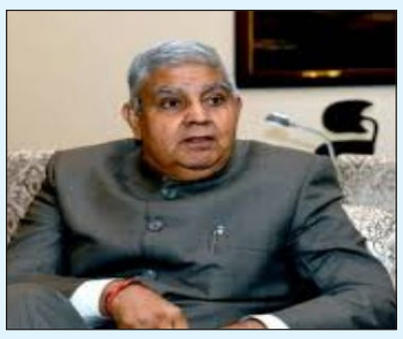
मुंबई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 के पुनर्विकास का वैकल्पिक मॉडल सुझाया है। उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजकर कहा है कि मौजूदा टर्मिनल को हटाने से पहले नया टर्मिनल तैयार किया जाए, ताकि निर्माण कार्य के दौरान उड़ान सेवाएं प्रभावित न हों। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, प्रस्ताव का उद्देश्य एयरलाइन परिचालन को बड़े पैमाने पर दूसरी जगह स्थानांतरित किए बिना पुनर्विकास कार्य पूरा करना है। योजना के अनुसार, सबसे पहले टर्मिनल-1B का पुनर्विकास किया जाएगा। इसके तैयार होकर चालू होने के बाद टर्मिनल-1A से संचालित उड़ानों को वहां स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद मौजूदा टर्मिनल-1A को हटाकर नए सिरे से बनाया जाएगा। इस चरणबद्ध व्यवस्था से यात्रियों और एयरलाइनों को होने वाली असुविधा कम करने की उम्मीद है। वर्ष 1964 में शुरू हुआ टर्मिनल-1 अब संरचनात्मक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण पुनर्विकास की प्रक्रिया से गुजरने वाला है। वर्ष 2017 में स्ट्रक्टवेल और 2024 में आईआईटी बॉम्बे की ओर से किए गए अलग-अलग मूल्यांकनों में भी इन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया था।

विदेशी एयरलाइनों की आपत्ति के बाद मार्च 2027 तक टला स्थानांतरण

दरअसल, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने शुरुआत में 25 अक्टूबर से बहरीन, दोहा, जेद्दा, काठमांडू, कुवैत, मस्कट और रियाद सहित 14 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों की उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, कई विदेशी एयरलाइनों ने इस योजना पर आपत्ति जताई। उनकी प्रमुख चिंताओं में नवी मुंबई एयरपोर्ट तक यात्रियों की पहुंच, मुंबई महानगर क्षेत्र के प्रमुख हिस्सों से कनेक्टिविटी और स्थानांतरण की व्यावहारिक व्यवस्था शामिल है। इन आपत्तियों के बाद प्रस्तावित बदलाव को मार्च 2027 तक टाल दिया गया है। टर्मिनल-1 से घरेलू उड़ानों का संचालन सुचारु बनाए रखने के लिए MIAL करीब 260 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने या अस्थायी रूप से रोकने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। दूसरी ओर, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और आकासा एयर ने अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के साथ मिलकर आने वाले महीनों में नवी मुंबई एयरपोर्ट से चरणबद्ध तरीके से अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन शुरू करने की तैयारी की है। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई के मौजूदा एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव कम होने की उम्मीद है, लेकिन परिवहन कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री फडणवीस का वैकल्पिक प्रस्ताव कितना प्रभावी साबित होगा और केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, इस पर विमानन क्षेत्र की नजरें टिकी हैं।

खास खबर

मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश हुए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, एम्स में भर्ती



नई दिल्ली। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह टहलते समय बेहोश होकर गिर पड़े और कुछ मिनट तक अचेत रहे। पहले उन्हें घर ले जाकर डॉक्टरों से जांच कराई गई, लेकिन हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराना पड़ा। जानकारी के मुताबिक सुरक्षाकर्मी उन्हें पीसीआर वाहन से घर लेकर पहुंचे। आईएलबीएस की मेडिकल टीम और एम्स के डॉक्टर संदीप सेठ ने उनकी जांच कर जरूरी चिकित्सा सहायता दी। इसके बाद उन्हें एंबुलेंस से एम्स ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक 75 वर्षीय धनखड़ को एम्स के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती किया गया है। फिलहाल कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं और जरूरी चिकित्सकीय जांच व उपचार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल भी सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्स के कार्डियक विभाग में भर्ती कराया गया था।

प्रधानमंत्री का 13-14 नवंबर को दो राज्यों का दौरा, कर्नाटक को देंगे 15600 करोड़ की सौगात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 और 14 नवंबर को कर्नाटक और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कर्नाटक में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी बिजली आपूर्ति परियोजनाएं, एलपीजी भंडारण सुविधा, रेलवे परियोजनाएं और कचरा प्रबंधन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। वह बेंगलुरु-मैंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 13 नवंबर को सुबह करीब 10:45 बजे बेंगलुरु में प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वह स्वर्ण जयंती प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखेंगे तथा केरल के तिरुवनंतपुरम में एस-व्यासा के नए परिसर का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:45 बजे तवरेकेरे से आईआईएम बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो यात्रा करेंगे और बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन करेंगे। करीब 1:15 बजे वह 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 3,470 करोड़ रुपये की लागत से विकसित पिंक लाइन केलेना अग्रहारा से तवरेकेरे तक विस्तारित है। इससे बेंगलुरु में शहरी परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, यात्रियों का समय बचेगा और रोजाना आवागमन आसान होगा। प्रधानमंत्री करीब 4,450 करोड़ रुपये की लागत से तैयार कोप्पल-द्वितीय और गदग-द्वितीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली पहुंचाने की परियोजना तथा करीब 1,370 करोड़ रुपये की लागत से विकसित बीदर सौर ऊर्जा क्षेत्र से बिजली पहुंचाने की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में क्रमशः करीब दो गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 2.5 गीगावाट सौर ऊर्जा को बिजली ग्रिड तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।



दिल्ली एनएसयूआई नेता छात्राओं को एनआरआई पुरुषों के पास भेजने के आरोपों में घिरा, अभाविप की एनआईए से जांच कराने की मांग



संवाददाता

नई दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज के एनएसयूआई उपाध्यक्ष अनस खान पर छात्राओं को पैसे और अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देकर एनआरआई पुरुषों के साथ भेजने से संबंधित कथित संदेश सामने आने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग की है। अभाविप का आरोप है कि एनआरआई प्रायोजित कार्यक्रम के नाम पर छात्राओं से संपर्क स्थापित किया जा रहा था और उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर चयन की बातें भी संदेशों में सामने आई हैं।

इस मामले में कॉलेज प्रशासन अनस खान को निलंबित कर चुका है। अभाविप ने कहा कि छात्राओं को आर्थिक प्रलोभन देकर इस तरह की गतिविधियों में शामिल करने का मामला संभावित मानव तस्करी और देह व्यापार जैसे संगठित अपराधों से जुड़े नेटवर्क की आशंका पैदा करता है। संगठन ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की व्यापक जांच कराई जाए, ताकि एनआरआई संपर्कों, आर्थिक लेन-देन और संभावित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की भूमिका का पता लगाया जा सके। अभाविप ने यह भी दावा किया कि पिछले माह एनएसयूआई से जुड़े व्यक्तियों द्वारा एक कार्यक्रम के लिए लड़कों को ले जाने से संबंधित इसी तरह की चैट सामने आई थी। संगठन ने लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या एनएसयूआई के कार्यक्रमों के पीछे आर्थिक प्रलोभन और संदिग्ध नेटवर्क काम कर रहे हैं। अभाविप ने वर्ष 2018 में एनएसयूआई के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान पर संगठन की एक महिला पदाधिकारी की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का भी उल्लेख किया। अभाविप ने इन घटनाओं को कांग्रेस और उसके छात्र संगठन के महिला सुरक्षा संबंधी दावों से जोड़कर सवाल उठाए। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि महिला अधिकारों और समानता की बात करने वाली कांग्रेस को अपने छात्र संगठन में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में एनएसयूआई की ओर से संबंधित पदाधिकारी को हटाए जाने के दावे के साथ पूर्व दिनांकित पत्र जारी किया गया है, जबकि संबंधित व्यक्ति के सोशल मीडिया स्टेटस में व्यक्तिगत कारणों से स्वयं इस्तीफा देने की बात कही गई है।

कुर्ला में दिनदहाड़े तीन गोलियां मारकर युवक की हत्या, बाइक सवार हमलावर फरार



संवाददाता

मुंबई। महानगर के कुर्ला इलाके में बुधवार दोपहर दिनदहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई। हलाव पुल के पास मकड़वाला कंपाउंड में बाइक सवार हमलावरों ने 40 वर्षीय विनोद पवार पर ताबड़तोड़ तीन गोलियां चलाईं।

गंभीर रूप से घायल विनोद को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना बुधवार दोपहर करीब 12:40 बजे वी.बी.नगर पुलिस थाना क्षेत्र में हुई। गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से कुर्ला परिसर में दहशत फैल गई और स्थानीय नागरिकों में भय का माहौल है। सूचना मिलते ही वी.बी.नगर पुलिस के अधिकारी और अन्य पुलिस टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। हमलावरों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

सिटी इंजीनियर विभाग ने अभियंताओं को दिया दिवाली का 'गिफ्ट'!

- एक साथ करीब 700 अभियंताओं के तबादला आदेश जारी, SIR में तैनात कर्मचारियों की बदली पर उठे सवाल
- बीएमसी आयुक्त के परिपत्र के बावजूद तबादले का आरोप, कई वार्डों में पद खाली, कामकाज प्रभावित होने की आशंका



संवाददाता

मुंबई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के सिटी इंजीनियर विभाग की ओर से एक साथ करीब 700 अभियंताओं के तबादला आदेश जारी किए जाने के बाद प्रशासनिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं। विभाग ने 26 वार्डों में एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक समय से कार्यरत अभियंताओं के ऑनलाइन तबादले किए हैं। लंबे समय से एक ही वार्ड में तैनात अभियंताओं के स्थानांतरण की प्रक्रिया को प्रशासनिक दृष्टि से उचित माना जा रहा है, लेकिन तबादलों के बाद खाली हुए पदों पर तत्काल नई नियुक्तियां नहीं होने से वार्डों के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तबादलों की प्रक्रिया में केवल अभियंताओं को ही निशाना बनाया गया है? यदि तबादले पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से किए गए हैं, तो जिन वार्डों से अभियंताओं को हटाया गया है, वहां उनकी जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? इसका एक उदाहरण बीएमसी के एच-पूर्व विभाग में देखने को मिल रहा है। यहां पांच उप अभियंताओं में से दो का तबादला कर दिया गया, लेकिन उनकी जगह नए उप अभियंताओं की नियुक्ति नहीं हुई। इसी तरह विभाग में कुल 10 कनिष्ठ अभियंताओं के पदों के मुकाबले पहले से केवल सात अभियंता कार्यरत थे। इनमें से दो के तबादले के बाद अब महज पांच कनिष्ठ अभियंताओं पर कामकाज की जिम्मेदारी रह गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि पांच अभियंता 10 बीट में कामकाज कैसे संभालेंगे? इसी तरह अन्य वार्डों में भी तबादले के बाद पद खाली रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

SIR में तैनात अभियंताओं के तबादले पर भी सवाल

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लगे अभियंताओं के तबादलों को लेकर उठ रहा है। बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने 6 अक्टूबर 2026 को जारी परिपत्र में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि SIR कार्य पूरा होने तक इस अभियान में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी (AERO) के रूप में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी न किए जाएं। परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि तबादलों के कारण विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके बावजूद सिटी इंजीनियर विभाग की ओर से SIR कार्य में तैनात कुछ अभियंताओं के तबादले किए जाने का आरोप है। इस मामले में बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब आयुक्त के परिपत्र में SIR कार्य पूरा होने तक तबादले रोकने के निर्देश दिए गए थे, तो क्या सिटी इंजीनियर विभाग ने इन निर्देशों का पालन किया? क्या तबादला सूची जारी करने से पहले SIR में तैनात अभियंताओं की जिम्मेदारियों की जांच की गई थी? और जिन वार्डों में अभियंताओं के पद खाली हुए हैं, वहां कामकाज सुचारु रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कब की जाएगी? बीएमसी प्रशासन को इन सवालों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही सिटी इंजीनियर विभाग को यह भी बताना चाहिए कि करीब 700 अभियंताओं के तबादलों के बाद वार्ड स्तर पर कामकाज और SIR अभियान प्रभावित न हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है।

संपादकीय



हर साल दमघोंटू होती दिल्ली

देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या हर साल सर्दियों के आगमन के साथ गंभीर रूप ले लेती है। अक्तूबर से फरवरी तक दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। प्रदूषण का स्तर कई बार खतरनाक सीमा पार कर जाता है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि दिल्ली को गैस चैंबर तक कहा जाने लगता है। इसके बावजूद इस समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। हर साल प्रदूषण बढ़ने पर सरकार ग्रैप के तहत अलग-अलग पाबंदियां लागू करती है। निर्माण कार्य रोक दिए जाते हैं, वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण की कोशिश होती है और सरकारी तथा निजी कार्यालयों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। लेकिन इन अस्थायी उपायों से प्रदूषण की समस्या समाप्त नहीं होती। इन प्रतिबंधों का सबसे अधिक असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ता है, जिनकी रोजी-रोटी प्रतिदिन के काम पर निर्भर होती है। निर्माण कार्य बंद होने से हजारों मजदूरों के सामने रोजगार और परिवार का भरण-पोषण करने का संकट खड़ा हो जाता है। उनकी आर्थिक स्थिति और भविष्य को लेकर सरकारों की चिंता भी अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है। दिल्ली के प्रदूषण की सबसे बड़ी वजहों में निजी वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या, निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक उत्सर्जन और खुले में कचरा तथा अन्य सामग्री जलाना शामिल हैं। एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में तीन करोड़ से अधिक निजी वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा की गुणवत्ता को लगातार प्रभावित करता है। इसके अलावा पराली जलाने को भी हर साल प्रदूषण का प्रमुख कारण बताकर राजनीतिक बहस छेड़ दी जाती है। हालांकि विभिन्न अध्ययनों में पराली के योगदान को सीमित बताते हुए वाहनों, निर्माण कार्यों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर अधिक ध्यान देने की जरूरत जताई गई है। दीपावली के दौरान भी दिल्ली की हवा की स्थिति बेहद चिंताजनक रही। अदालत के निर्देशों और पटाखों को लेकर लागू प्रतिबंधों के बावजूद बड़े पैमाने पर आतिशबाजी हुई। इसके बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। दीपावली की रात दिल्ली का एक्यूआई 376 तक पहुंच गया, जबकि अगले दिन सुबह कई इलाकों में यह 400 के पार दर्ज किया गया। राजधानी के 15 से अधिक इलाकों में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया, जबकि 35 इलाकों में एक्यूआई 300 से 400 के बीच रहा। सामान्य तौर पर एक्यूआई का 100 तक रहना अपेक्षाकृत संतोषजनक माना जाता है। इससे ऊपर जाने पर हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ जाते हैं। प्रदूषण का संकट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के अनेक शहरों में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। इंदौर जैसे स्वच्छता के लिए पहचाने जाने वाले शहर में भी दीपावली के दौरान प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ने की खबरें सामने आईं। विभिन्न रिपोर्टों में वायु प्रदूषण को देश में समय से पहले होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण बताया गया है। यह स्थिति बताती है कि प्रदूषण अब केवल पर्यावरण से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा से संबंधित गंभीर चुनौती बन चुका है। ऐसे में केवल पराली जलाने वाले किसानों को जिम्मेदार ठहराना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किसानों के सामने फसल अवशेषों के निपटान की व्यावहारिक और आर्थिक चुनौतियां हैं। सरकारों को उन्हें आधुनिक मशीनों, आर्थिक सहायता और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए पराली प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण पर सख्त निगरानी की आवश्यकता है। दिल्ली में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, प्रदूषण के मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप के बजाय केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। यह समस्या किसी एक राज्य या सरकार की सीमा में बंधी नहीं है, बल्कि पूरे एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। चीन जैसे देशों ने बड़े शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए व्यापक नीतियां और सख्त नियंत्रण व्यवस्था लागू की है। भारत को भी दूसरे देशों के सफल उपायों से सीख लेकर अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रभावी रणनीति तैयार करनी चाहिए। प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को इस दिशा में साझा जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रदूषण से निपटने के लिए केवल आपातकालीन प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है। सालभर निगरानी, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान, जवाबदेही तय करने और योजनाओं को जमीन पर लागू करने की जरूरत है। दिल्ली और देश के दूसरे शहरों को हर साल दमघोंटू हवा के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता।

कैंसर की दवाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से मरीजों को मिली बड़ी राहत

सौरभ वार्ष्णेय



कैंसर का नाम सुनते ही किसी भी परिवार के सामने सबसे पहले जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो जाता है। यह ऐसी बीमारी है, जिसका इलाज न केवल मरीज को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ता है, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक कमर भी तोड़ देता है। इलाज की लंबी प्रक्रिया, महंगी जांच, अस्पतालों का खर्च और जीवनरक्षक दवाओं की कीमतें पहले से परेशान परिवारों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होतीं। ऐसे में कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में भारी कटौती होना निश्चित रूप से लाखों मरीजों और उनके परिजनों के लिए राहत भरी खबर है। लेकिन इस फैसले के पीछे छिपी सच्चाई देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और दवा कारोबार पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कैंसर की 137 दवाओं की कीमतें कम की गई हैं। दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की नई कीमतें जारी की हैं। इनमें 679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50 प्रतिशत से अधिक घटाए गए हैं। कुछ दवाओं की कीमतों में तो 96.45 प्रतिशत तक की कमी की गई है। अनुमान है कि इस कदम से मरीजों को सालाना करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि अब तक कैंसर के इलाज के नाम पर आम आदमी की जेब पर कितना बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा था। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 22 सितंबर को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कैंसर की दवाओं की रिटेल कीमत और अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच भारी अंतर पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत की टिप्पणी थी कि 2,700 रुपये की दवा मरीज को 27,000 रुपये में मिलना दिनदहाड़े डकैती और नरसंहार जैसा है। न्यायालय की यह नाराजगी केवल दवाओं की कीमतों को लेकर नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल था, जिसमें गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों की मजबूरी को कारोबार और मुनाफे का अवसर बना लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद 17 अक्टूबर को नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर कंपनियों का ट्रेड मार्जिन 30 प्रतिशत निर्धारित किया। इसी निर्णय के बाद कीमतों में कमी का रास्ता साफ हुआ। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों ने भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। समिति में देश के प्रमुख कैंसर विशेषज्ञों, चिकित्सकों, अस्पतालों के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों और व्यापारिक मार्जिन को तर्कसंगत बनाना था।

यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जीवन बचाने वाली दवाओं के कारोबार में इतना अधिक मुनाफा कैसे संभव हुआ? क्या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज की विवशता का फायदा उठाना उचित है? दवा उद्योग का अपना आर्थिक पक्ष है। कंपनियों को अनुसंधान, उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, वितरण और नई दवाओं के विकास पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन इन सभी खर्चों के नाम पर ऐसी कीमतें वसूलना, जिन्हें आम आदमी वहन ही न कर सके, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। दवा कोई सामान्य उपभोक्ता वस्तु नहीं है। यह किसी व्यक्ति के जीवन, उसके परिवार की उम्मीद और उसके भविष्य से जुड़ी होती है।

भारत जैसे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आज भी आर्थिक स्थिति से प्रभावित होती है। संपन्न परिवार बेहतर अस्पतालों और महंगे उपचार का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के सामने अक्सर इलाज जारी रखने या घर की आर्थिक स्थिति बचाने के बीच कठिन चुनाव करने की नौबत आ जाती है। कई बार लोग जमीन, मकान और पुश्तैनी संपत्ति तक बेच देते हैं। कुछ परिवार कर्ज में डूब जाते हैं तो कुछ आर्थिक असमर्थता के कारण उपचार अधूरा छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे हालात में दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण केवल आर्थिक नीति का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदनशीलता का प्रश्न है। हालांकि, केवल कीमतें घटा देना ही पर्याप्त नहीं होगा। सरकार और संबंधित नियामक संस्थाओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित कीमतों का लाभ वास्तव में मरीजों तक पहुंचे। दवा दुकानों, अस्पतालों और वितरकों के स्तर पर नियमित निगरानी होनी चाहिए। यदि कोई कंपनी या विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनी रहे और कीमतों पर नियंत्रण के नाम पर उनकी आपूर्ति प्रभावित न हो।

विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाई गई 137 दवाओं की सूची को समय-समय पर अपडेट करने का निर्णय भी महत्वपूर्ण है। कैंसर के उपचार में लगातार नई दवाएं और तकनीकें सामने आ रही हैं। इसलिए मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था भी समय और जरूरत के अनुसार विकसित होनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नई और प्रभावी दवाएं भी आम मरीजों की पहुंच से बाहर न हों। सरकारी अस्पतालों में कैंसर उपचार की सुविधाओं का विस्तार, जांच की सुलभता और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही आवश्यक है।

दरअसल, किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे मरीजों के लिए दवाओं की कीमत कम होना महज एक आर्थिक राहत नहीं, बल्कि जीवन की उम्मीद को मजबूत करने वाला कदम है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने इस दिशा में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। लेकिन इस राहत को स्थायी व्यवस्था में बदलना सरकार, दवा कंपनियों और नियामक संस्थाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है। जीवन बचाने वाली दवाएं मुनाफे का असीमित माध्यम नहीं बननी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य केवल कारोबार नहीं, बल्कि मानव जीवन की रक्षा होना चाहिए। कैंसर से लड़ रहे मरीजों को बीमारी से संघर्ष करना चाहिए, दवाओं की कीमतों और आर्थिक शोषण से नहीं। यही इस फैसले का वास्तविक संदेश और एक संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था की कसौटी है।



एल.आई.सी
भारतीय जीवन बीमा से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या समाधान हेतु संपर्क करें।
-भारत सिंह
मो. 9967255741

महत्वपूर्ण सूचना
विज्ञापन प्रति के स्वीकृति पूर्व एहतियातन बरती जाने के बावजूद, उसमें अंतर्भूत बाते जाँचना संभव नहीं है। ऐसी अंतर्भूत बातों के लिए दैनिक स्वर्णिम प्रदेश के अंतर्गत समाचार पत्र या प्रकाशनों में आनेवाली कंपनियां, संस्थाए या व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ हुए किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं है।

सबके साथ के कारण स्वच्छता में सिरमौर रहता है इंदौर : कैलाश विजयवर्गीय

संवाददाता



इंदौर। स्वच्छता में लगातार आठ साल से देश में अव्वल रहने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर इस बार भी दिल्ली में 11 नवंबर को होने वाले पुरस्कार समारोह के लिए निमंत्रण मिला है। दिल्ली से आए निमंत्रण को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर की स्वच्छता को शहरवासियों का साथ मिलता है। इसी कारण इंदौर स्वच्छता के मामले में लगातार नंबर वन रहा है।

विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी और उनकी इस अवधारणा को इंदौर ने आत्मसात किया। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा पर काम करती है। अब इंदौर के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र भी स्वच्छता के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे बुधवार को दिल्ली में होने वाले पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। दरअसल, इस बार इंदौर को स्वच्छता प्रीमियर लीग में शामिल किया गया है, लेकिन इस बार नगर निगम की देखरेख में स्वच्छता के मामले में आगे बढ़े देपालपुर को पुरस्कार मिलने की उम्मीद है। पिछले साल देपालपुर की रैंकिंग 1710वीं थी, लेकिन इस बार उसे टॉप थ्री में स्थान मिलने की संभावना जताई जा रही है। पिछले साल स्वच्छता प्रीमियर लीग में शामिल शहरों के साथ अन्य शहरों लोगों को जागरूक कर घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को भी प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इन्हीं प्रयासों के चलते देपालपुर ने स्वच्छता के मामले में उल्लेखनीय सुधार किया है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। इस उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त करने मंगलवार को महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि और निगम अधिकारी दिल्ली रवाना हुए। उज्जैन नगर निगम ने इस बार स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई है। निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, कचरा प्रबंधन और नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। सफाई मित्रों की मेहनत, निगम अधिकारियों-कर्मचारियों के समर्पण और शहरवासियों के सहयोग से यह उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि इस बार एमआर-5 और गोंदिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नए प्लांट लगाए गए। चप्पल-जूतों के कचरे के निस्तारण के लिए भी अलग प्लांट स्थापित किए गए हैं। ग्रीन वेस्ट के प्रबंधन के लिए पृथक प्लांट लगाया गया। महाकाल मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों के आसपास बीटवार योजना बनाकर कचरे का निस्तारण किया गया। शहर में नागरिकों की भागीदारी से गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के लिए भी अभियान चलाया गया। निगम के अनुसार, इन प्रयासों से स्वच्छता व्यवस्था में सुधार हुआ और उज्जैन को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। दूसरे नंबर से पुरस्कार की दौड़ से बाहर हुआ भोपाल बुधवार, 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के विजेता शहरों को सम्मानित करेंगी। सुपर स्वच्छ लीग में शामिल इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को न्योता मिल गया है, लेकिन भोपाल-बैरसिया को बुलावा नहीं मिला है। इससे माना जा रहा है कि भोपाल-बैरसिया इस बार स्वच्छ शहर जोड़ी का पुरस्कार हासिल नहीं कर पाएंगे, जबकि पिछली बार इस जोड़ी ने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया था।

शीतकाल के लिए बंद हो गए केदारनाथधाम के कपाट

संवाददाता



केदारनाथधाम। हिमालय की गोद में बसे बाबा केदानाथ के पवित्र धाम के कपाट शीतकाल के लिए पारंपरिक अनुष्ठान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आज सुबह 8:30 बजे बंद किए गए। बाबा केदार की उत्सव डोली (चल विग्रह उत्सव डोली) अब ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर जाएगी।

ओंकारेश्वर मंदिर सर्दियों के दौरान भगवान का निवास स्थान होता है। कपाट बंद होने का यह अवसर भाई दूज के दिन पड़ा। मंदिर के लगभग छह महीने तक बंद रहने से पहले देश-विदेश से आए भक्त भगवान शिव के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहां एकत्र हुए। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी गंगाधर लिंग महाराज ने बताया कि कपाट बंद करने की प्रक्रिया निर्धारित धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार पूरी की गई। उन्होंने कहा, आज भाई दूज है। सुबह भगवान का महाभिषेक किया गया, विशेष प्रार्थनाएं हुईं और सुबह 8:30 बजे मंदिर के मुख्य कपाट बंद कर दिए गए। अब बाबा केदार की उत्सव डोली को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाएगा, जहां सर्दियों के महीनों में भगवान की पूजा-अर्चना की जाएगी। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि कपाट बंद होने के समारोह और उसके बाद उत्सव डोली की यात्रा के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। तोमर ने बताया कि गद्दी (देवता का आसन) को यहां से ऊखीमठ स्थित शीतकालीन गद्दी तक ले जाया जाएगा। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज डोली के लिए 'गार्ड ऑफ ऑनर' और मोबाइल गार्ड तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि डोली के रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख पड़ावों पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। अगले साल मंदिर के फिर से खुलने तक जिला पुलिस बल केदारनाथ में तैनात रहेगा, साथ ही भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की एक टुकड़ी भी तैनात रहेगी। तोमर ने कहा कि ऊखीमठ में शीतकालीन तीर्थयात्रा के दौरान सुरक्षा यातायात और मार्ग प्रबंधन के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से दर्शन के लिए ओंकारेश्वर मंदिर जाने की अपील की।

आज का राशिफल

मेष: कार्यस्थल पर आपकी सूझबूझ से बड़ी समस्या हल होगी। व्यापार में उन्नति होगी, नए ग्राहक जुड़ेंगे। परिजनों के साथ यात्रा की योजना बन सकती है। धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक रूप से शांत रहेंगे।

वृषभ: दफ्तर में रूटीन कामों में मन लगाएं, विवाद टालें। व्यापार में निवेश करते समय बहुत सतर्क रहें। जीवनसाथी के साथ मधुरता बनाए रखें। धन के मामलों में बजट के अनुसार ही काम करें। पेट का ध्यान रखें, सात्विक भोजन लें।

मिथुन: बौद्धिक क्षमता के बल पर दफ्तर में पहचान बनेगी। व्यापार में नए सौदों से बड़ा मुनाफा संभव है। दोस्तों के साथ समय बिताने से मन खुश होगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, नया स्रोत मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी।

कर्क: दफ्तर में अधिकारियों की बातों को प्राथमिकता दें। व्यापारिक गतिविधियों में सावधानी से काम लें। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। अनावश्यक खर्च रोकें, धन संचय पर ध्यान दें। सेहत सामान्य रहेगी, नियमित योग-ध्यान करें।

सिंह: आपके साहस और पराक्रम से विरोधी शांत रहेंगे। व्यापारिक विस्तार के नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में धार्मिक या मांगलिक चर्चा हो सकती है। आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, लाभ होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।

कन्या: दफ्तर में आपके काम की गुणवत्ता की प्रशंसा होगी। व्यापार में रुके काम गति पकड़ेंगे, मुनाफा होगा। अपनों के साथ रिश्ते और गहरे और मजबूत होंगे। रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक रूप से खुश रहेंगे।

तुला: नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। साझेदारी के व्यापार में अच्छा आर्थिक फायदा होगा। दांपत्य जीवन में सुख और सौहार्द बढ़ेगा। वित्तीय लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, आय बढ़ेगी। सेहत बढ़िया रहेगी, स्फूर्ति महसूस करेंगे।

वृश्चिक: दफ्तर में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। व्यापारिक फैसलों में किसी अनुभवी से सलाह लें। वाणी में नम्रता रखें, परिवार में विवाद न होने दें। फिजूलखर्च से बचें, बजट नियंत्रित रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर्याप्त आराम लें।

धनु: दफ्तर में नई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, पद बढ़ेगा। व्यापार में नए निवेश से बड़ा फायदा संभव है। संतान की प्रगति से मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा। आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा। सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी बनी रहेगी।

मकर: कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, काम समय पर होंगे। व्यापारिक फैसलों में दूरदर्शिता का फायदा मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सौहार्द और शांति रहेगी। धन संचय में सफलता मिलेगी, स्थिति मजबूत होगी। सेहत अच्छी रहेगी, दिनचर्या ठीक रखें।

कुंभ: आपकी बुद्धिमत्ता से सभी कठिन काम आसानी से निपटेंगे। व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी, नया सौदा होगा। मित्रों और सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा। आर्थिक पक्ष काफी सुदृढ़ रहेगा, लाभ होगा। सेहत बहुत अच्छी रहेगी, मन में उत्साह रहेगा।

मीन: दफ्तर में अधिकारियों की सलाह से काम में लाभ होगा। व्यापार में अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। परिवार का माहौल शांतिपूर्ण और सुखद रहेगा। धन आगमन सुचारू रहेगा, बचत में वृद्धि होगी। मानसिक शांति महसूस होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

पालघर के चिंचानी में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

संवाददाता

बछड़े को मारने के बाद वन विभाग ने बिंबारेपाड़ा के पास लगाया था पिंजरा, तेंदुए के हमलों से जिले में दो लोगों की हो चुकी है मौत



पालघर। दहानू तालुका के चिंचानी गांव के रिहायशी इलाकों में लगातार दिखाई दे रहे तेंदुए को वन विभाग ने आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए के पकड़े जाने से दहशत में जी रहे स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। रविवार रात तेंदुए ने एक ग्रामीण के पशुबाड़े में घुसकर बछड़े को मार डाला था। इस घटना के बाद वन विभाग ने चिंचानी के बिंबारेपाड़ा के पास पिंजरा लगाया था, जिसमें तेंदुआ फंस गया। पिछले कुछ महीनों से दहानू तालुका और आसपास के तटीय गांवों में रिहायशी इलाकों के नजदीक तेंदुओं की आवाजाही बढ़ने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, रात के समय कई इलाकों में तेंदुए दिखाई देते रहे हैं। तनाशी और बावड़े में भी मवेशियों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। इन हमलों में बछड़े, बकरियां, भेड़ और मुर्गियां तेंदुओं का शिकार बने हैं। बुधवार सुबह तेंदुए के पकड़े जाने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण पिंजरे के पास जमा हो गए। लोग तेंदुए को देखने के लिए उत्सुक नजर आए।

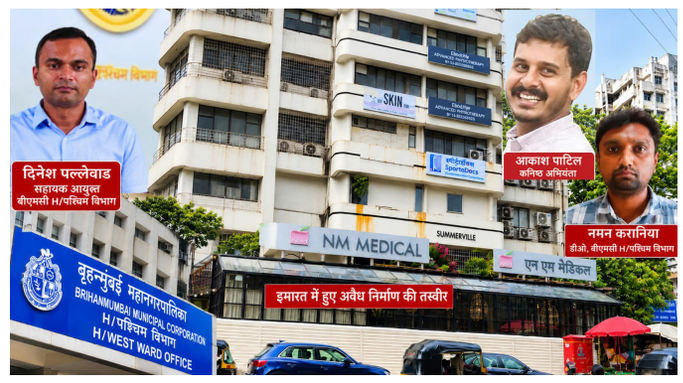
तेंदुए के हमलों में दो लोगों की मौत

पालघर जिले में तेंदुओं की बढ़ती गतिविधियां अब गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। जिले में तेंदुए के हमलों से अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। लगातार सामने आ रही घटनाओं के चलते ग्रामीणों ने वन विभाग से संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पिंजरे लगाने और गश्त व निगरानी बढ़ाने की मांग की है। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। विशेष रूप से रात के समय अकेले बाहर निकलने और खेतों में काम करने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी जंगली जानवर की संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना दें।

बीएमसी H/पश्चिम में अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले कनिष्ठ अभियंता आकाश पाटील पर कब होगी कार्रवाई?

संवाददाता

समरविले बिल्डिंग के अतिक्रमण पर सहायक आयुक्त दिनेश पल्लेवाड और पदनिर्देशित अधिकारी नमन करानिया की भूमिका पर सवाल, कथित वसूली और बंदरबांट की जांच की मांग



मुंबई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के विभिन्न वार्डों में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें कथित संरक्षण देने और वसूली के आरोप लगातार प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुंबई शहर और उपनगरों में बड़ी संख्या में अवैध निर्माणों को नोटिस जारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होना बीएमसी की व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। इमारत एवं कारखाना विभाग के अभियंताओं पर बीएमसी हर महीने करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ताजा मामला बीएमसी H/पश्चिम विभाग के बांद्रा पश्चिम स्थित 14वें और 33वें रोड जंक्शन, लिंकिंग रोड के पास समरविले बिल्डिंग (एनएम मेडिकल सेंटर के ऊपर) का है। यहां आवासीय इमारत के भूतल की खुली जगह में कथित अतिक्रमण और निर्माण नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है।

अग्निसुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी का मुद्दा भी उठाया गया है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से कनिष्ठ अभियंता आकाश पाटील, पदनिर्देशित अधिकारी नमन करानिया और सहायक आयुक्त दिनेश पल्लेवाड की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सूत्रों का दावा है कि उक्त निर्माण को संरक्षण देने के लिए कनिष्ठ अभियंता आकाश पाटील ने कथित तौर पर मोटी रकम वसूली और इस रकम का बंटवारा सहायक आयुक्त दिनेश पल्लेवाड तथा पदनिर्देशित अधिकारी नमन करानिया के बीच हुआ। इसी कथित लेन-देन के चलते संबंधित निर्माण पर कार्रवाई नहीं किए जाने के सवाल उठ रहे हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह केवल एक अवैध निर्माण का मामला नहीं, बल्कि बीएमसी की निगरानी और जवाबदेही व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल है। इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कर संबंधित अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट की जानी चाहिए। वहीं, बीएमसी के विजिलेंस विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। अक्सर शिकायत की जांच उसी विभाग या संबंधित अधिकारी के पास भेजे जाने की शिकायत सामने आती है, जिसके खिलाफ मामला उठाया गया होता है। ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे संभव होगी? आखिर विजिलेंस विभाग स्वतंत्र रूप से जांच क्यों नहीं करता? क्या उसे हर मामले में महानगरपालिका आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त के आदेश का इंतजार करना पड़ता है? आखिर समरविले बिल्डिंग के कथित अतिक्रमण पर कार्रवाई कब होगी? कनिष्ठ अभियंता आकाश पाटील के खिलाफ बीएमसी प्रशासन कब कदम उठाएगा? सहायक आयुक्त दिनेश पल्लेवाड और पदनिर्देशित अधिकारी नमन करानिया की भूमिका की स्वतंत्र जांच कब होगी? बीएमसी प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और शिकायत पर की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड सार्वजनिक करना चाहिए।

वन मंत्री गणेश नाइक के सरकारी बंगले में लगी आग, दमकल विभाग ने पाया काबू

संवाददाता

मंत्रालय के सामने स्थित 'पावनगढ़' बंगले में AC यूनिट से आग लगने की आशंका, कोई हताहत नहीं



मुंबई। दक्षिण मुंबई में मंत्रालय के सामने स्थित महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक के सरकारी आवास 'पावनगढ़' में बुधवार को अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आग सरकारी बंगले में लगे एयर कंडीशनिंग (AC) यूनिट से शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के दौरान बंगले से धुआं उठता दिखाई दिया। दमकलकर्मियों को आग बुझाने में जुटा देख आसपास मौजूद लोगों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू

नगर निकाय अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार, दमकल विभाग ने आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि, आग से बंगले को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। घटना के समय वन मंत्री गणेश नाइक बंगले में मौजूद थे या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है। मंत्रालय के ठीक सामने स्थित सरकारी आवास में आग लगने की घटना के बाद सुरक्षा और आग लगने के कारणों को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है।

दो सप्ताह में साफ होगी दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के विलय की तस्वीर: रुपाली ठोंबरे पाटील

संवाददाता

शरद पवार और सुनेत्रा पवार के फैसले पर सहमति जताई, सुनील तटकरे पर साधा निशाना, बोलीं- अजितदादा की इच्छा पूरी होती दिख रही है



पुणे। महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार और शरद पवार गुट के विलय को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। अजित पवार गुट के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे की ओर से विलय का मुद्दा उठाए जाने और दोनों गुटों के नेताओं की शरद पवार से मुलाकातों के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है।

इसी बीच अजित पवार गुट की नेता रुपाली ठोंबरे पाटील ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि अगले दो सप्ताह में दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के विलय को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। मीडिया से बातचीत में ठोंबरे पाटील ने कहा कि अजित पवार के रहते भी विलय की चर्चाएं चल रही थीं और अब करीब सात महीने बाद यह मुद्दा फिर सामने आया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार और सुनेत्रा पवार विलय को लेकर जो निर्णय लेंगे, वह उन्हें स्वीकार होगा। उनके मुताबिक, अजितदादा की भी ऐसी इच्छा थी और अब वह पूरी होती दिखाई दे रही है। इस दौरान उन्होंने सुनील तटकरे पर भी निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब पहले विलय की चर्चा हुई थी, तब उन्होंने इसका विरोध क्यों किया था? नौ महीने बाद फिर यह मुद्दा उठने से कार्यकर्ताओं के मन में पहले जैसी नाराजगी और सवाल पैदा होंगे या नहीं, इसका जवाब तटकरे को देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेता पदों के लिए चुप्पी साधे हुए हैं और इसके लिए भी तटकरे को जिम्मेदार ठहराया। ठोंबरे पाटील ने अजित पवार के विमान हादसे की जांच का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हादसे को लेकर महाराष्ट्र की जनता के मन में कई सवाल हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर सभी सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए।

रामदास कदम और महेश थोरवे की ओर से इस मामले में उठाए गए सवालों को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। वहीं, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट के राष्ट्रवादी कांग्रेस में तीसरा गुट बनने के दावे पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। गोकुळ दूध संघ के चुनाव पर बोलते हुए ठोंबरे पाटील ने कहा कि वह इस मामले में वकील के तौर पर अपनी कानूनी भूमिका रखेंगी। उन्होंने दावा किया कि प्रशासनिक अधिकारियों को मतदान का अधिकार देने का मुद्दा कानूनी जांच के दायरे में आता है और इस मामले में अदालत का फैसला महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने मौजूदा चेयरमैन पद की स्थिति को अस्थायी बताते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया में हुई देरी का लाभ उठाया गया है। इसके अलावा चंद्रकांत दादा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। सत्ता में रहते हुए धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में पहले ही काफी कटुता बढ़ चुकी है और नेताओं को अपने बयानों में संयम रखना चाहिए।

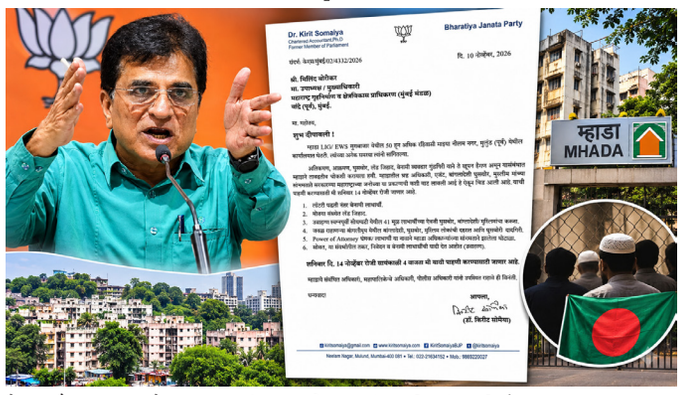
किरीट सोमैया का सनसनीखेज आरोप: म्हाडा के 110 फ्लैटों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा! एंटॉप हिल में 'लैंड जिहाद' का दावा, 14 नवंबर को करेंगे दौरा

संवाददाता

मुंबई। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में म्हाडा के आवासों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और कम आय वर्ग (LIG) के लिए बनाए गए म्हाडा के 110 फ्लैटों पर कथित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है। उनका दावा है कि इन फ्लैटों के लिए मूल आवेदन हिंदू लाभार्थियों के नाम पर किए गए थे, लेकिन बाद में पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से दूसरे लोगों ने इनका नियंत्रण हासिल कर लिया। सोमैया ने इस संबंध में दस्तावेजों के साथ म्हाडा और संबंधित मंत्रियों को शिकायत देकर मामले की जांच तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

अविनाश के नाम आवंटित फ्लैट पर दूसरे व्यक्ति के कब्जे का दावा

सोमैया ने अपने आरोपों के समर्थन में अविनाश रविधोने के नाम पर आवंटित फ्लैट का उदाहरण देते हुए दावा किया कि उस पर मंसूरी जुनैद मोहम्मद का कब्जा है। इसी तरह उन्होंने शकील अहमद सिद्दीकी, रिजवान मोहम्मद हुसैन, साजिद अली कादिर अब्दुल बाते, नसरीन रमजान शेख, मुनीरा रिजवान, मुजमिल शेख, अंसारी हफीजुर, खान सद्दाम हुसैन, मोहम्मद जहांगीर शेख और मोहम्मद सिद्दीकी शेख सहित अन्य लोगों के नाम भी शिकायत में शामिल किए हैं। भाजपा नेता का आरोप है कि गलत तरीके से हिंदू लाभार्थियों के नाम पर आवेदन कर सरकारी आवासों का लाभ दूसरे लोगों ने हासिल किया। उन्होंने इस पूरे मामले में बेनामी लेन-देन और म्हाडा के कुछ अधिकारियों तथा एजेंटों की कथित मिलीभगत की भी जांच की मांग की है।



14 नवंबर को म्हाडा परिसर का दौरा करेंगे सोमैया

म्हाडा के मुंबई मंडल के मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर को लिखे पत्र में सोमैया ने बताया कि नूराबाजार स्थित म्हाडा आवासीय परिसर के 50 से अधिक निवासी उनसे मिले थे।

इन लोगों ने कथित अवैध कब्जे, अतिक्रमण, घुसपैठियों की मौजूदगी, बेनामी लेन-देन और धमकियों जैसी शिकायतें की हैं। सोमैया ने म्हाडा प्रशासन से आवंटन रिकॉर्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेजों और वास्तविक लाभार्थियों की तत्काल जांच करने की मांग की है। उन्होंने 14 नवंबर को स्वयं परिसर का दौरा कर स्थिति का जायजा लेने की घोषणा की है।

हालांकि, जिन लोगों पर बांग्लादेशी नागरिक होने या अवैध रूप से रहने के आरोप लगाए गए हैं, उनकी नागरिकता और कानूनी स्थिति की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में आरोपों की वास्तविकता संबंधित सरकारी एजेंसियों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अब देखना होगा कि म्हाडा प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है।

गन्ना मजदूरों के बच्चों की होगी विशेष स्वास्थ्य जांच स्वास्थ्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर ने दिए निर्देश

संवाददाता

चीनी मिलों और गन्ना कटाई वाले क्षेत्रों में चलेगा 'बालसंजीवनी' अभियान, बच्चों को मौके पर ही मिलेंगी स्वास्थ्य और टीकाकरण सुविधाएं



मुंबई। महाराष्ट्र में गन्ना कटाई के लिए परिवारों के साथ दूसरे जिलों और क्षेत्रों में पलायन करने वाले मजदूरों के बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाएगी।

मंगलवार को स्वास्थ्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर ने ऐसे सभी बच्चों की विशेष स्वास्थ्य जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से 'बालसंजीवनी' अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से चीनी मिलों के परिसरों और गन्ना कटाई वाले खेतों के आसपास बनी अस्थायी बस्तियों में पहुंचकर बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य में चीनी मिलों का पेराई सीजन शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में गन्ना मजदूर अपने परिवारों के साथ कारखाना परिसरों और खेतों में अस्थायी रूप से रहने लगे हैं। इन मजदूरों के साथ आने वाले छोटे बच्चों को समय पर स्वास्थ्य जांच, उपचार और टीकाकरण की सुविधा मिलना मुश्किल हो जाता है। मजदूरों के लंबे समय तक घर से दूर रहने और काम की व्यस्तता के कारण बच्चों को नियमित रूप से स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना भी संभव नहीं हो पाता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्यमंत्री बोर्डीकर ने कहा कि बच्चों को बीमारी के दौरान इलाज के लिए भटकना न पड़े और उन्हें स्वस्थ जीवन मिल सके, यही अभियान का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के अंतर्गत पलायन करने वाले प्रत्येक बच्चे की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसमें कुपोषण, एनीमिया, बाल विकास में देरी, जन्मजात विकृतियों और संक्रामक बीमारियों की जांच कर जरूरत के अनुसार उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवक, आशा स्वयंसेविकाएं, आंगनवाड़ी सेविकाएं और चीनी मिल प्रबंधन को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को लिखित निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार राज्य की सभी चीनी मिलों की सूची तैयार करने, मजदूरों के अस्थायी निवास स्थलों का सर्वेक्षण करने और इन्हीं स्थानों पर बच्चों के आवश्यक टीकाकरण की व्यवस्था करने को कहा गया है। इस पहल से गन्ना मजदूर परिवारों के बच्चों को उनके अस्थायी निवास स्थान पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

सूखे की चिंता न करें, सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है: कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे

संवाददाता

इंदापुर के घोरपडवाडी में किसान के घर पहुंचकर मनाई दिवाली, जून तक पेयजल की व्यवस्था का भरोसा



पुणे। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने बुधवार को इंदापुर तालुका के घोरपडवाडी गांव में किसान हणमंत बापुराव लावंड के घर पहुंचकर किसानों के साथ दिवाली का फराल किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद कर सूखे की स्थिति, पेयजल, सिंचाई और पशुओं के चारे की समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूखे के संकट में राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। किसानों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पेयजल, खेती के पानी और पशुओं के चारे के लिए तत्काल और दीर्घकालीन उपाय किए जाएंगे। गांव पहुंचते ही कृषि मंत्री भरणे किसान लावंड के घर के सामने स्थित पशुबाड़े में गए। उन्होंने लावंड परिवार से मवेशियों और चारे की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। किसान परिवार ने बताया कि घर में उपलब्ध गन्ने की पूरी फसल पशुओं के चारे के लिए रखी गई है और मक्का खरीदकर भी चारे की व्यवस्था की जा रही है। मंत्री ने बकरियों और मुर्गियों के बाड़े का भी निरीक्षण किया। इसके बाद परिवार की महिलाओं ने उनका औक्षण किया। उन्होंने घर के सदस्यों और उपस्थित किसानों से आत्मीयता से बातचीत की तथा सभी के साथ दिवाली का फराल और पोहे खाए। इस अवसर पर भरणे ने कहा कि वे राज्य के कृषि मंत्री होने के साथ-साथ किसानों के प्रतिनिधि भी हैं। वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं, इसलिए किसानों की परेशानियों और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को समझते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला वर्ष चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जून महीने तक पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। जिन क्षेत्रों में पीने के पानी की किल्लत है, वहां आवेदन मिलने पर तत्काल टैंकर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

जिन क्षेत्रों में पानी के स्रोत उपलब्ध हैं, वहां चारा फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से चारा फसलों के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पशु शिविर शुरू करने के मुद्दे पर भी अगले एक-दो महीनों में विचार किया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के खातों में दिवाली के लिए पांच हजार रुपये अग्रिम सहायता के रूप में जमा किए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ के मानदंडों और एसडीआरएफ के माध्यम से अधिकतम संभव सहायता देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार के नेतृत्व में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। इस दौरान उन्होंने दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार को भी याद किया। भरणे ने कहा कि सूखे का संकट बड़ा जरूर है, लेकिन इसे भूजल स्तर बढ़ाने और जल संरक्षण के स्थायी उपाय करने के अवसर के रूप में भी देखना चाहिए। कृषि और जलसंधारण विभाग के माध्यम से तालाबों से गाद निकालने, छोटे बांध बनाने और जल निकासी संरचनाओं की मरम्मत जैसे कार्य किए जाएंगे। रोजगार गारंटी योजना के तहत इन कार्यों के साथ पाणंद सड़कों का निर्माण भी कराया जाएगा, जिससे खेत मजदूरों को रोजगार मिल सके। उन्होंने किसानों को खेत तालाब और ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने की भी सलाह दी। इस अवसर पर कृषि विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

Kerala HC Questions Prolonged Suspension Of Kalady University Students

KOCHI: The Kerala High Court on Wednesday questioned the prolonged suspension of students at Kalady university, asking why the institution continued to insist on an apology after keeping them out of classes for more than two months. Considering a petition challenging the suspension of 16 students, the court made sharp oral observations about the university's disciplinary approach and posted the matter for detailed arguments on Friday.



'You have suspended the students for three months. What further apology is needed?' the court asked, questioning whether the university's anger had still not subsided and what more it expected from the students. The court clarified that it was not justifying everything the students had done. However, it questioned the need to prolong disciplinary action when they had already remained outside the institution for over 60 days.

Observing that they were students, the court also wondered what present-day senior politicians might have done during their own student years. The university submitted that the disciplinary action followed allegations that students had manhandled the Vice-Chancellor and participated in other protests.

The court also sought an explanation for the registration of two FIRs, noting that a second case was registered two days after the first. Responding to questions about how both cases could stand, the university said they concerned separate incidents.

The students have sought withdrawal of their suspensions and permission to appear for examinations. In their amended writ petition, they contended that they had 60 per cent attendance and were eligible to take the examinations.

The university syndicate had earlier offered to revoke the suspension of 12 students if they submitted written apologies. The students rejected that condition. The court's observations came during preliminary consideration of the petition. It will hear detailed submissions on Friday on the students' challenge to the continuing disciplinary action.

Air quality in several parts of UP showing signs of gradual recovery

LUCKNOW: After the Diwali festival, air quality in various regions of Uttar Pradesh indicated a slow improvement, although many cities continued to be engulfed in dangerous pollution levels.

Lucknow AQI: Following a peak of 245, classified as 'poor', on November 9, the air quality in Lucknow improved to 172 (moderate) by November 10, as reported by the Central Pollution Control Board. Red Zone Cities: Following the festival, at least seven areas in Uttar Pradesh such as Noida, Ghaziabad, Sonbhadra (Anpara), Khurja, Baghpat, Gajraula, and Bulandshahr experienced their AQI spike over 300 into the 'red zone' (very poor to severe). Visibility and Weather: Thick fog and dropping temperatures significantly affected visibility throughout the state, with no visibility noted in Varanasi and limited visibility in Bareilly (100 meters) and Lucknow (300 meters). Contributing Factors: Meteorological conditions such as light winds and decreasing winter temperatures, along with leftover firecracker smoke, vehicle emissions, and construction dust, have hindered the dispersion of pollutants. Earlier, the air



quality in many cities of Uttar Pradesh deteriorated rapidly on Monday, November 9, the day after Diwali. Due to the effect of smoke from fireworks and firecrackers, the Air Quality Index (AQI) in seven cities of the state crossed 300, i.e. reaching the red zone, which is considered serious for health. According to the data of the Central Pollution Control Board (CPCB), Anpara of Sonbhadra was the most polluted city in the state on Monday, the day after Diwali. The AQI here was recorded at 355. Meanwhile, Noida recorded an AQI of 332 and Khurja 331. Ghaziabad also recorded an air quality index of 324. Furthermore, Baghpat, Gajraula, and Bulandshahr also recorded AQIs above 300.

Administration Begins Demolition of Illegal Portion of Jailed TMC Leader Jahangir Khan's Building in Falta

KOLKATA: Taking strict action against jailed Trinamool Congress leader Jahangir Khan, the district administration on Wednesday commenced the demolition of the illegal portion of his multistory building located in Serampore under Falta in South 24 Parganas district. On Wednesday morning, administrative officials arrived at the building accompanied by a large police contingent. Several senior administrative officials, including the Block Development Officer, were present at the spot. Following an internal inspection of the premises, the demolition process was initiated. This decisive step by the administration has created a stir across the entire area. According to administrative sources, Jahangir Khan is accused of holding massive properties, both in his own name and as benami assets. Complaints allege that he has encroached upon government land to carry



out illegal constructions at multiple locations. The process of taking legal action against all such illegal structures has now begun. It is reported that the demolition of the illegal section of the Serampore building was started in strict compliance with government directives. It is noteworthy that numerous cases of land grabbing and the accumulation of illegal properties against Jahangir Khan have been a topic of discussion for a long time. He is currently lodged in jail. Amidst the ongoing investigation into the allegations and subsequent administrative actions, the district administration has now directly launched a drive to raze the illegal constructions. To avert any untoward incident during the operation, a heavy police force was deployed in the area since Wednesday morning. Police officers kept a close watch on the entire situation. The administrative drive also drew significant curiosity among the local residents. All eyes are now focused on whether the administration will take similar stringent action against other illegal constructions held in the name of Jahangir Khan or his benami properties in the coming days.

भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेच्या विकासात बेटांवरील मत्स्यव्यवसाय केंद्रस्थानी

नवी दिल्ली: भारताला अंदाजे 11,099 किलोमीटरची किनारपट्टी आणि जवळपास 24 लाख चौरस किलोमीटरचे विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) लाभले आहे. त्यामुळेच भारत विशाल सागरी संसाधनांच्या पाठबळाने समृद्ध असलेला देश ठरला आहे. देशाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात अंदाजे 58.6 लाख मेट्रिक टन सागरी मासेमारीची क्षमता आहे. हे क्षेत्र देशभरातील सुमारे 50 लाख कोळी बांधवांच्या उपजीविका टिकवून ठेवण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आले आहे. यासोबतच अन्न सुरक्षा, पोषण, रोजगार, उत्पन्न निर्मिती आणि निर्यातीद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नातही हे क्षेत्र महत्त्वाचे योगदान देत आले आहे. आजमितीला भारत जागतिक पातळीवर मासेमारी आणि जलपरिसंस्थेच्या आधारे उत्पादन घेणाऱ्या आघाडीच्या देशांमध्ये समाविष्ट आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षादरम्यान भारताची सागरी खाद्यान्नाची निर्यात सुमारे 73,890 कोटी रुपये इतकी होती. यातून भारताच्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत आणि जागतिक सीफूड व्यापारात या क्षेत्राचे वाढते महत्त्व अधोरेखित होते.

भारताच्या मासेमारी क्षेत्राचे उत्पादन केंद्रित उपक्रमाचे स्वरुप बदलून त्याला राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा एक बहुआयामी, तंत्रज्ञानाधारित आणि मूल्याभिमुख आधारस्तंभ म्हणून विकसित करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. याच अनुषंगाने केंद्र सरकारने 2015 पासून मासेमारी क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ केली असून, प्रमुख योजना आणि कार्यक्रमांच्या माध्यमातून या क्षेत्रात 39,272 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. मासेमारी क्षेत्राच्या विकास प्रक्रियेला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने बेटांच्या प्रदेशांसाठी मोठी गुंतवणूक करावी असे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत (PMMSY) प्रस्तावित केले गेले आहे. याअंतर्गत अंदमान आणि निकोबार बेटांसाठी 218 कोटी रुपयांची गुंतवणूक मंजूर करण्यात आली आहे. तर लक्षद्वीपसाठी 175 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या सागरी क्षेत्रांमधील मासेमारीच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून घेण्याची केंद्र सरकारची वचनबद्धता यातून दिसून येते.

अमेरिकेच्या समन्सपासून चीनच्या भ्रामक प्रचाराला सडेतोड प्रत्युत्तर

नवी दिल्ली: आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भारताने आपली भूमिका ठामपणे स्पष्ट केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत अमेरिका, चीन, रशिया, युक्रेन, इस्त्रायल, बांगलादेश आणि नेपाळसह विविध देशांशी संबंधित घडामोडींवर भारताची भूमिका मांडली. विशेषतः अमेरिकेतील न्यायालयीन समन्स, धार्मिक स्वातंत्र्यावरील यूएससीआयआरएफचे आरोप आणि चीनशी संबंधित दिशाभूल करणाऱ्या व्हिडिओंचा मुद्दा या पत्रकार परिषदेच्या केंद्रस्थानी राहिला.

अमेरिकेतील न्यूयॉर्क न्यायालयात खलिस्तानी फुटीरतावादी गुरपतवंत सिंह पन्नू याने दाखल केलेल्या दिवाणी याचिकेच्या अनुषंगाने भारत सरकारला समन्स बजावण्यात आल्याच्या वृत्तांवर परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंगचे माजी प्रमुख सामंत गोयल यांच्यासह भारतीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर करण्यात आलेले आरोप मनगढंत आणि दुर्भावनापूर्ण असल्याचे रणधीर जायसवाल यांनी स्पष्ट केले. हा खटला तुच्छ, निराधार आणि अनुचित असल्याचे सांगत भारताने आरोप फेटाळून लावले. भारताच्या भूमिकेनुसार, देशात कोणत्याही न्यायालयीन दस्तऐवजाची अधिकृत बजावणी केवळ भारताच्या नामनिर्दिष्ट केंद्रीय प्राधिकरणामार्फत म्हणजेच कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या माध्यमातूनच होऊ



शकते. या प्रकरणाचा संबंध 2025 मध्ये पन्नूच्या कथित हत्येच्या कटाशी जोडलेल्या आरोपांशी असून, अमेरिकेचा न्याय विभाग निखिल गुप्ता आणि विकास यादव यांच्याविरोधातील प्रकरणाची चौकशी करत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित चिंतांची तपासणी करण्यासाठी भारताने यापूर्वीच उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. यूएससीआयआरएफच्या अहवालावर भारताचे प्रत्युत्तरभारतात गुरुद्वारे, चर्च आणि मशिदींसह धार्मिक स्थळांना लक्ष्य केले जात असल्याच्या अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या (यूएससीआयआरएफ) दाव्यांवर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.रणधीर जायसवाल यांनी यूएससीआयआरएफच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्न उपस्थित करत या संस्थेला पक्षपाती, अपुरी माहिती असलेली आणि राजकीय अजेंड्याने प्रेरित असल्याचे म्हटले. अमेरिकेत धार्मिक स्थळांवर होणारे हल्ले, तसेच भारतीय समुदायावरील द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि वांशिक हल्ल्यांबाबत यूएससीआयआरएफ आणि त्याच्या आयुक्तांनी सातत्याने मौन बाळगल्याचा आरोपही भारताने केला.

दिल्ली-एनसीआरमधील वाढत्या प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश

नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर परिसरातील वाढत्या वायुप्रदूषणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान सरकारला कडक निर्देश दिले आहेत. जुन्या तसेच नियमबाह्य वाहनांना दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रवेश करण्यापासून आणि त्यांची वाहतूक रोखण्यासाठी आतापर्यंत कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहोचल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नोंदवले. प्रदूषणाची परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी तातडीने प्रभावी पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान सरकारांसह दिल्ली महानगरपालिका आणि दिल्ली पोलिसांकडून उत्तर मागवले आहे. संबंधित सर्व पक्षांना आपले प्रतिज्ञापत्र आणि उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्य



सरकारांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी सध्या राबवण्यात येत असलेल्या उपाययोजना, तसेच प्रदूषण कमी करण्यासाठी आखलेल्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन योजनांची माहिती न्यायालयाला द्यावी लागणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणासाठी केवळ स्थानिक वाहनांचा वाटा नसून, शेजारील राज्यांतून येणारी अवजड व्यावसायिक तसेच खासगी वाहनेही प्रदूषणात भर घालत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे संबंधित राज्य सरकारे आणि यंत्रणा न्यायालयासमोर कोणत्या उपाययोजना मांडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सोशल मीडियावरून फ्रान्समध्ये द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न

पॅरिस: फ्रान्समध्ये महागाई आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनांदरम्यान सोशल मीडियावर बनावट पोस्ट आणि व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात प्रसारित करण्यात आले. युरोपीय महासंघाच्या (ईयू) एका अंतर्गत अहवालानुसार, रशियाशी संबंधित नेटवर्कने स्थलांतरितांविरोधात द्वेष पसरवून नागरिकांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला.याशिवाय, इस्त्रायल आणि अमेरिकेतील 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (मॅगा) चळवळीशी संबंधित समाजमाध्यमांवरील खात्यांनीही या निदर्शनांबाबत चुकीची माहिती पसरवली. फ्रान्स सरकारची प्रतिमा कमकुवत करणे हा या मोहिमेमागील उद्देश होता. मात्र, या नेटवर्कने निदर्शने घडवून आणली नाहीत, तर आधीपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाचा फायदा घेतला. रशियाशी संबंधित नेटवर्कने समाजमाध्यमांवर अनेक खोटे दावे प्रसारित केले. यामध्ये स्थलांतरितांकडून निदर्शकांवर बलात्कार होत असल्याचे तसेच देशात दहशतवादी हल्ले होण्याची शक्यता असल्याचे दावे करण्यात आले. या पोस्टच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये भीती आणि स्थलांतरितांविरोधात संताप निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, १६ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान रशियासमर्थक गटांच्या सर्वाधिक पाहिल्या गेलेल्या १० पोस्टना एकूण २८ लाखांहून अधिक वेळा पाहण्यात आले. याच काळात अमेरिकेतील 'मॅगा' चळवळीशी संबंधित व्यक्तींच्या सर्वाधिक पाहिल्या गेलेल्या १० पोस्टना ४.९ कोटींपेक्षा अधिक



वेळा पाहण्यात आले. त्याचप्रमाणे, इस्त्रायली अधिकारी, सरकारी खाती आणि प्रभावशाली व्यक्तींनी केलेल्या अशाच १० पोस्टना ३.५ कोटींपेक्षा अधिक वेळा पाहण्यात आले.'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (मॅगा) ही अमेरिकेतील उजव्या विचारसरणीची चळवळ असून, ती राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या राजकीय भूमिकेला पाठिंबा देते. दरम्यान, फ्रान्सचे पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांनी देशात सातत्याने सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी उद्योग संघटना आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली.या बैठकीत नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवणे आणि वेतनाशी संबंधित समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. महागाईने त्रस्त असलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार किमान वेतनात पुन्हा एकदा वाढ करण्याचा विचार करत आहे. जगभरातील हिंसाचार आणि विरोधी निदर्शनांवर लक्ष ठेवणाऱ्या एसीएलईडी या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, १५ सप्टेंबर ते ३० ऑक्टोबर या कालावधीत युरोपातील ३१ देशांमध्ये महागाई आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रश्नांवरून १,७०० हून अधिक निदर्शने झाली. या आंदोलनांची सुरुवात फ्रान्समधून झाली होती.फ्रान्समध्ये महागाई आणि शिक्षण व्यवस्थेबाबत नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष रस्त्यावर उतरला. त्यानंतर या आंदोलनाचे लोण स्पेन आणि इटलीसारख्या देशांमध्येही पसरले.या देशांमध्ये हजारो नागरिकांनी घरांच्या वाढत्या किमती आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या महागाईविरोधात निदर्शने केली. त्यामुळे नागरिकांच्या वाढत्या आर्थिक अडचणी अनेक देशांतील सरकारांसमोर मोठे आव्हान ठरत आहेत.युरोपातील अनेक देशांमध्ये येत्या काही दिवसांत आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. स्पेनमध्ये कामगार संघटनांनी ११ नोव्हेंबर रोजी संप पुकारला आहे.

बॉक्स ऑफिस पर कायम है 'रामायण' का दबदबा, लगातार बढ़ रही कमाई

रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'रामायणः भाग 1' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। वीकेंड के बाद कारोबारी दिनों में भी फिल्म की कमाई में मजबूती बनी हुई है। रिलीज के छह दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत के साथ विदेशी बाजारों में भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने छठे दिन यानी मंगलवार को भारत में 94.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके साथ ही फिल्म का घरेलू नेट कलेक्शन 440.45 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 526.50 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, विदेशी बाजारों में छठे दिन फिल्म ने करीब 35 करोड़ रुपये कमाए। इसके साथ ही विदेशों में कुल कमाई 297 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस तरह फिल्म का दुनियाभर का कुल ग्रॉस कलेक्शन 823.50 करोड़ रुपये हो गया है।



इससे पहले सोमवार को फिल्म ने 107.50 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शानदार प्रदर्शन किया था। मंगलवार को कमाई में करीब 12.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म का कारोबार मजबूत बना हुआ है। नितेश तिवारी के निर्देशन और नमित मल्होत्रा के निर्माण में बनी इस फिल्म में साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल और लारा दत्ता भी अहम भूमिकाओं में हैं।

ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आया सलमान का डायलॉग

सलमान खान की आगामी फिल्म 'मातृभूमिः मे वॉर रेस्ट इन पीस' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में है। लंबे समय से टल रही यह फिल्म अब 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान के साथ पहली बार चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी। ट्रेलर को दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। जहां कुछ लोगों ने फिल्म के एक्शन और कहानी की तारीफ की, वहीं सलमान के एक संवाद को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं।



दरअसल, ट्रेलर के एक दृश्य में सलमान चीनी सैनिक से बातचीत करते हुए कहते हैं, चलो इसे ठीक करते हैं, ब्रो। पीस आउट। युद्ध जैसे तनावपूर्ण माहौल में उनके इस हल्के-फुल्के अंदाज वाले संवाद को कई दर्शकों ने अटपटा बताया है। इस संवाद के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स ने इसकी तुलना सलमान के पहले वायरल हुए संवाद सोनम, इट्स डन, ब्रो से भी की।

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि सैन्य तनाव की स्थिति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कितना उचित है। वहीं, कुछ यूजर्स ने फिल्म के संवाद लेखन और उसे मंजूरी देने वालों की आलोचना की। कुछ लोगों ने तो सलमान को अभिनय से संन्यास लेने की सलाह तक दे डाली।

गौरतलब है कि 'मातृभूमि' 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' से होगा।

पांच करोड़ रुपये की गुमशुदगी पर आधारित है 'द ब्लाइंड गेम'

अभिनेता अर्जुन रामपाल और प्रियामणि की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'द ब्लाइंड गेम' 11 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 फ्री 5 पर स्ट्रीम होगी। दिवंगत निर्देशक संगीत सिवन के निर्देशन में बनी यह उनके करियर की आखिरी फिल्म है। इस वजह से फिल्म उनके प्रशंसकों और सिनेमा जगत के लिए खास महत्व रखती है। फिल्म में अर्जुन और प्रियामणि के अलावा आकाश माखीजा और रोहित चंदेल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। क्रिसमस की एक रहस्यमयी रात की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म की कहानी दोस्तों के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमती है। पांच करोड़ रुपये की गुमशुदगी और एक कुख्यात अपराध सरगना की दुनिया में फंसने के बाद इन दोस्तों की जिंदगी बदल जाती है। मामले की जांच शुरू होने पर एक आईपीएस अधिकारी के सामने कई चौंकाने वाले राज खुलते हैं। कथित आत्महत्या, अलग-अलग बयान और छिपे हुए सच कहानी में सस्पेंस को



और गहरा करते हैं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, दोस्तों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि किस पर भरोसा किया जाए। अर्जुन रामपाल के मुताबिक, फिल्म की कहानी में लगातार बदलते नजरिए, धोखे और किरदारों के फैसले दर्शकों को रोमांचक अनुभव देंगे। फिल्म के निर्माता कुशाग्र शर्मा और सृष्टि शर्मा ने भी उम्मीद जताई है कि इसकी रहस्यमयी कहानी दर्शकों को पसंद आएगी। फिल्म का निर्माण थंडरस्काई एंटरटेनमेंट और सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है। इसके निर्माता सृष्टि शर्मा, कुशाग्र शर्मा, दीपक मुकुट और हुनर मुकुट हैं।

ओवरथिंकिंग के कारण उड़ जाती है नींद? अपनाएं ये 6 तरीके

दिनभर काम, घर की जिम्मेदारियां और भागदौड़ के बाद जब रात में आराम करने का समय मिलता है, तब कई लोगों का दिमाग और ज्यादा चलने लगता है। कभी दिनभर की गुजरी हुई बातें याद आती हैं, तो कभी भविष्य की चिंता और पुरानी गलतियों को लेकर विचार आने लगते हैं। बिस्तर पर लेटने के बाद भी मन शांत नहीं होता और नींद आने में देर हो जाती है। इसे ओवरथिंकिंग कहा जाता है। कभी-कभार ऐसा होना सामान्य है, लेकिन अगर लगातार विचारों के कारण नींद और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगे, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। दिन के समय सारा ध्यान काम, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियों में बंटा रहता है। रात में बाहरी गतिविधियां कम हो जाती है, ऐसे में मन उन बातों पर लौट आता है जिन्हें दिन में सोचने का समय नहीं मिला। तनाव, भविष्य की चिंता, अनियमित नींद और सोने से पहले मोबाइल चलाने की आदत भी इस परेशानी का कारण हो सकती है। कई बार नींद न आने की चिंता भी एक चक्र बना देती है। व्यक्ति सोचता रहता है कि उसे जल्दी सोना चाहिए, लेकिन यही दबाव उसे और बेचैन करता है।

ओवरथिंकिंग रोकने के 6 आसान तरीके

सोने से पहले मन की बातें लिखें

अगर दिमाग में एक साथ कई विचार आ रहे हैं, तो उन्हें डायरी में नोट करें। कौन-सी बात परेशान कर रही है और उसके लिए



कल क्या किया जा सकता है, इसे लिखें। इससे विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है।

सोने से पहले मोबाइल से बनाएं दूरी

बिस्तर पर लेटकर लगातार रील्स देखना, खबरें पढ़ना या काम के मैसेज चेक करना दिमाग को सक्रिय रखता है। सोने से लगभग 30 मिनट पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं और इसकी जगह हल्की किताब पढ़ें या संगीत सुनें।

धीमी सांस लेने की कोशिश करें

आराम से बैठें या लेट जाएं। नाक से धीरे-धीरे सांस लें और बिना जोर लगाए धीरे-धीरे छोड़ें। कुछ मिनट तक ऐसा करें। ध्यान सांस पर रखने से विचारों से थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाने में मदद मिलती है।

हर विचार का जवाब ढूंढने की कोशिश न करें

रात में किसी समस्या का तुरंत समाधान निकालना जरूरी नहीं है। खुद से कहें कि इस पर कल शांत मन से विचार करेंगे। यह भी समझें कि हर विचार सच नहीं होता और हर चिंता का समाधान उसी समय मिलना जरूरी नहीं है।

सोने और जागने का समय तय रखें

हर दिन लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग, किताब पढ़ना या गुनगुने पानी से नहाना जैसी आदतें स्लीप क्वालिटी को बढ़ाती है। शाम को चाय-कॉफी का सेवन भी सीमित रखें, कोशिश करें कि 6 बजे के बाद इनका सेवन न करें।

दिन में चिंता के लिए समय निकालें

अगर रात में बार-बार काम, रिश्तों या भविष्य की चिंता सताती है, तो दिन में 10-15 मिनट का समय उन बातों पर सोचने के लिए रखें। इस दौरान देखें कि किन समस्याओं पर आप कुछ कर सकते हैं और किन बातों को छोड़ देना बेहतर है।

कब एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए?

अगर ओवरथिंकिंग लगातार बनी रहती है, नींद बार-बार टूटती है, दिनभर थकान रहती है या चिंता के कारण काम और रिश्ते प्रभावित होने लगते हैं, तो मनोवैज्ञानिक या मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ से सलाह लें। जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग भी मददगार हो सकती है।

हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता ChatGPT, इन बातों का रखें ध्यान

पिछले कुछ वक्त में ChatGPT भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आजकल लोग पढ़ाई से लेकर ऑफिस प्रोजेक्ट और किसी भी तरह के क्रिएटिव काम के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मनोरंजन के लिए भी AI खूब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ध्यान रखें कि यह हर जगह सुरक्षित सलाह नहीं देता। अगर आप इस पर पूरी तरह भरोसा करते हैं, तो किसी दिन यह आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। आज हम आपको ऐसे ही 5 बड़े मामलों के बारे में बताएंगे जिनमें AI चैटबॉट से सलाह लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.



हेल्थ से जुडी जानकारी

ChatGPT कुछ बीमारियों या उनके लक्षणों के बारे में जानकारी दे सकता है, लेकिन अगर आप बुखार, सिरदर्द या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ChatGPT से सलाह लेते हैं, तो यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। AI कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए सही इलाज के लिए हमेशा डॉक्टर से ही सलाह लें।

निजी जानकारी में सलाह

अपनी सैलरी या बैंक डिटेल जैसी निजी जानकारी कभी भी किसी AI चैटबॉट के साथ शेयर न करें क्योंकि इससे आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है, तो आपकी सारी निजी जानकारी हैक हो सकती है। हो सकता है कि कुछ जगहों पर यह अच्छी वित्तीय सलाह दे, लेकिन आपको इसके साथ कोई भी पर्सनल डिटेल या डाक्यूमेंट्स भी शेयर नहीं करने है।

गैर-कानूनी जानकारी

कुछ लोग तो ChatGPT का यूज करके अवैध या खतरनाक जानकारी निकालने की भी ट्राई करते हैं, लेकिन यह न सिर्फ गलत बल्कि आपको कानूनी मुसीबत में भी डाल सकता है क्योंकि ऐसे मामलों में OpenAI के सख्त फिल्टर काम करते हैं और इस तरह की एक्टिविटी पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, यानी अगर आप ChatGPT से कुछ गैर-कानूनी पूछते हैं तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है।

मेंटल हेल्थ एडवाइस

अगर आप डिप्रेशन जैसी समस्या से गुजर रहे हैं तो एआई का ज्यादा इस्तेमाल न करें क्योंकि AI हल्की-फुल्की मोटिवेशनल बातें तो कर सकता है लेकिन यह किसी थेरेपिस्ट का विकल्प नहीं है, बल्कि ऐसी कंडीशन में आपको किसी प्रोफेशनल काउंसलर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए।

लीगल एडवाइस

अगर आप किसी सामान्य कानून के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो ChatGPT इस मामले में आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी कानूनी नोटिस के बारे में जानना चाहते हैं या कोर्ट केस के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। आपको ऐसी किसी कंडीशन में हमेशा किसी वकील से सलाह लें क्योंकि ChatGPT द्वारा दी गई जानकारी अधूरी या गलत हो सकती है। AI चैटबॉट के सर्च बार के नीचे कंपनी ने खुद यह लिखा हुआ है कि ChatGPT कैन मेक मिस्टेक्स'।

तनाव से राहत और बेहतर जीवन के लिए जरूरी है योग

आज की भाग-दौड़ भरी, तनाव और टारगेट से भरी जिंदगी में योग सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि ज़रूरत बन गया है। ऑफिस का दबाव, सोशल मीडिया का असर, पारिवारिक जिम्मेदारियां और करियर की चिंताएं इंसान को हर तरफ से जकड़ लेती हैं। ऐसे में योग के आसन, प्राणायाम और ध्यान मानसिक शांति देते हैं और चिंता, डिप्रेशन व एंग्जायटी को कम करने में मददगार साबित होते हैं। लंबे समय तक बैठे रहने वाली जॉब और कम सक्रिय जीवनशैली मांसपेशियों की अकड़न, कमर दर्द, मोटापा और डायबिटीज जैसी समस्याओं को जन्म देती हैं, जिन्हें योग से काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

लचीलापन बढ़ाने, पोस्चर सुधारने में सहायक

योग इन सब स्थितियों में राहत दिलाता है। योग के जरिये शरीर में लचीलापन बढ़ता है, पोस्चर सुधरता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। वहीं हार्ट बीट काबू में रहती है। साथ ही तनाव के कारण होने वाली सूजन नहीं होती और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसलिए हर व्यक्ति को योग करने की जरूरत है। भले वह शारीरिक रूप से इसकी जरूरत महसूस करता हो या न करता हो। तनावपूर्ण जिंदगी जीने वाले लोग अगर प्रत्यक्ष तौर पर कई सारी चिंताओं से परेशान नहीं दिखते, तो भी आशंका रहती है कि किसी भी क्षण उनमें ये सारी समस्याएं अपना असर दिखा सकती हैं। इसलिए अलर्ट रहकर योग के जरिये इस तरह की आशंकाओं को निर्मूल करते रहना चाहिए।

गहरी नींद, बेहतर रिश्ते

योग करने से बेहतर नींद आती है जिससे न सिर्फ शरीर को शांति महसूस होती है बल्कि जीवनशैली को भी बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए योग करना बहुत फायदेमंद होता है। योग करने से मेलाटॉनिन हार्मोन का स्तर संतुलित होता है, जिससे अनिद्रा यानी इंसोमेनिया जैसी समस्याएं दूर होती हैं। हम दिनभर ऊर्जा से लबालब



रहते हैं जो लोगों के साथ रिश्ते सहज और दोस्ताना बनाने में मददगार हैं। दरअसल, मेडिटेशन और यौगिक विधियों द्वारा हम खुद के भीतर झांकने की कोशिश करते हैं। किसी आपाधापी में धैर्य और आत्मसंयम बनाये रहते हैं। इससे हमारे घर, परिवार और प्रोफेशनल रिश्ते तो संतुलित रहते ही हैं, हमारे खुद के साथ भी रिश्ते संतुलित होते हैं। वास्तव में योग हममें तुरंत रिएक्ट करने की जगह रिस्पोंड करने की आदत डालता है।

तन, मन का संतुलन

योग को सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं कहना चाहिए बल्कि यह एक लाइफस्टाइल थैरेपी है जो हमारे तन, मन और आत्मा तीनों को संतुष्ट रखती है। तीनों के बीच एक बेहतर संतुलन रखती है और सबसे बड़ी बात यह है कि योग करने में हमारे सिर्फ समय के और थोड़े से शारीरिक प्रयासों के अलावा कुछ और खर्च नहीं होता। इसलिए तनाव और दबाव से भरी जिंदगी में हर किसी को योग करना चाहिए। इससे हमें महंगी दवाओं की गिरफ्त में नहीं जाना पड़ता। मेडिसिन के बिना भी हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। कहा भी गया है योग करो, रोग से दूर रहो और दुनिया के साथ साथ खुद से भी जुड़ो। योग से ये तिहरे स्तर के लाभ होते हैं।

स्ट्रेस फ्री वर्ल्ड के लिए योग ज्ञान

विश्व को चिंताओं और तनाव से छुटकारा दिलाने में भारत के योग ज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है, यह बात पूरी दुनिया मानती है। योग, ध्यान तथा आयुर्वेद दुनिया को तनाव से मुक्ति दिलाने में बड़े मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। योग सिर्फ धार्मिक या पारंपरिक विरासत नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध मानव जीवन को शांति का तोहफा है। दुनिया ने योग को मानसिक और शारीरिक तनाव से राहत का साधन माना है। अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे सभी विकसित देशों में आज न सिर्फ लोग घरों और पार्कों में हर तरफ योग करते दिखेंगे बल्कि अस्पतालों, स्कूलों, कार्पोरेट कार्यालयों और सेना के बैरकों में भी अब योग को एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में अपना लिया गया है। योग का मूल सिद्धांत है स्थिरता, श्वास की गहराई और मन का संतुलन। ये तीनों चीजें किसी भी व्यक्ति के तनाव को जड़ से पकड़ती है और उसे उखाड़ बाहर करती हैं। इससे व्यक्ति खुशी और संतोष अनुभव करता है।

आज दुनियाभर में फैल चुके माइंडफुलनेस, विपश्यना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, वास्तव में इन सब जरूरी योग ज्ञान की जड़ें भारत में हैं। यही वजह है कि आज गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों को ध्यान सिखा रही हैं ताकि वो तनाव कम करें और अधिक उत्पादक बनें। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज ने इस संबंध में रिसर्च की हैं और भारतीय ज्ञान विधियों को तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याओं के इलाज में कारगर पाया है।

पटना नगर निगम का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड NSE पर सूचीबद्ध, जुटाए करीब 200 करोड़ रुपये

- बिहार में शहरी विकास को नई वित्तीय ताकत, बाजार क्षेत्रों के पुनर्विकास सहित 15 परियोजनाओं पर खर्च होगी राशि



संवाददाता

पटना। बिहार के शहरी विकास और नगरपालिका वित्तपोषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है। पटना नगर निगम (PMC) की ओर से जारी पहले म्युनिसिपल बॉन्ड को 10 नवंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) पर सूचीबद्ध किया गया। पटना में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में यह लिस्टिंग हुई।

बिहार में किसी शहरी स्थानीय निकाय की ओर से पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। इसे शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी बाजार से धन जुटाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इस बॉन्ड का बेस इश्यू साइज 100.03 करोड़ रुपये रखा गया था, जबकि ग्रीन शू विकल्प के तहत 99.96 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने का प्रावधान किया गया। निजी प्लेसमेंट के जरिए जारी इस बॉन्ड को संस्थागत निवेशकों से बेस इश्यू के मुकाबले दो गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला। इससे म्युनिसिपल बॉन्ड में निवेशकों की बढ़ती रुचि और भरोसे का संकेत मिला है। बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल पटना नगर निगम की ओर से कुल 199.99 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाने वाली 15 परियोजनाओं के वित्तपोषण में किया जाएगा। इन परियोजनाओं के तहत शहर के विभिन्न बाजार क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाएगा। इससे शहरी सुविधाओं, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

अन्य नगर निगमों को भी बॉन्ड जारी करने की सलाह

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और राज्य को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पटना नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की NSE पर लिस्टिंग के साथ लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि जुटाने का रास्ता खुला है। उन्होंने इसे बिहार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉन्ड से प्राप्त धनराशि ऐसी परियोजनाओं में लगाई जानी चाहिए, जिनसे नियमित आय हो सके। राज्य के अन्य नगर निगमों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। उन्होंने विभागों को अपनी संपत्तियों और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर राजस्व बढ़ाने के अवसर तलाशने की सलाह दी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, बॉन्ड और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल से जुटाई गई राशि का निवेश ऐसी परियोजनाओं में होना चाहिए, जो कर्ज चुकाने के बाद भी अतिरिक्त राजस्व पैदा कर सकें।

NSE ने बिहार सरकार की पहल को सराहा

NSE के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीषकुमार चौहान ने इस पहल को बिहार की शहरी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए पूंजी बाजार का उपयोग करने की दिशा में ऐतिहासिक पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष बिहार सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने NSE के आउटरीच कार्यक्रम के तहत मुंबई का दौरा किया था। इस दौरान पूंजी बाजार की व्यवस्था और इसके माध्यम से धन जुटाने की संभावनाओं को समझा गया था। उन्होंने इस पहल को सफल बनाने में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार और पटना नगर आयुक्त यश पाल मीना के योगदान की सराहना की। चौहान ने कहा कि NSE शहरी स्थानीय निकायों को पूंजी बाजार के माध्यम से वित्त जुटाने में सहायता देने और टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

देश में 23 नगर निगमों ने जारी किए 32 म्युनिसिपल बॉन्ड

देश में अब तक 23 नगर निगमों की ओर से 32 म्युनिसिपल बॉन्ड इश्यू जारी किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से कुल लगभग 4,740.33 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में ही 14 इश्यू के जरिए करीब 1,756.44 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई। यह आंकड़े शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड को वित्त जुटाने के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में मिल रही स्वीकृति को दर्शाते हैं। पटना नगर निगम का पहला बॉन्ड बिहार को देश के म्युनिसिपल बॉन्ड बाजार से जोड़ने की दिशा में अहम पहल है। इससे राज्य के अन्य नगर निकायों के लिए भी पूंजी बाजार से वित्त जुटाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। समारोह में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नितीश मिश्रा, पटना की महापौर सीता साहू, उपमहापौर रेशमी कुमारी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

योगी सरकार की दोहरी सौगात: 1,146 युवाओं को नियुक्ति पत्र, 4,300 किसान परिवारों को 215 करोड़ की सहायता



संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार, 11 नवंबर को राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं और किसान परिवारों को बड़ी सौगात दी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के माध्यम से राजस्व विभाग में चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वहीं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 लाभार्थियों को कुल 215 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकारी नौकरी केवल रोजगार का अवसर नहीं, बल्कि जनता के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से पूरी ईमानदारी, मेहनत और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना कर्मचारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए और कामकाज में जवाबदेही बनाए रखना जरूरी है। लंबे समय से चयन प्रक्रिया का इंतजार कर रहे 1,146 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने से उनके परिवारों में खुशी का माहौल रहा। नए कर्मचारियों की तैनाती से राजस्व विभाग के कामकाज को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 लाभार्थियों को 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई। यह योजना खेती-किसानी से जुड़े परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। दुर्घटना के बाद परिवारों पर आने वाले आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार की यह सहायता प्रभावित परिवारों के लिए राहत का माध्यम बनेगी। इस तरह कार्यक्रम में एक ओर युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर मिला, तो दूसरी ओर हजारों किसान परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई।

गोवर्धन पूजा पर सदर विधायक पंकज गुप्ता ने किया गौ पूजन



संवाददाता

उन्नाव, उत्तर प्रदेश। गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर सदर विधायक पंकज गुप्ता ने पीडी नगर स्थित हनुमंत जीव आश्रम पहुंचकर विधि-विधान से गौ पूजन किया। इस दौरान उन्होंने गौ माता को तिलक लगाकर फूल-माला अर्पित की और आरती उतारकर क्षेत्र की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

पूजा-अर्चना के बाद विधायक ने गायों को गुड़, हरा चारा और अन्य खाद्य सामग्री खिलाई तथा गौ सेवा कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने आश्रम में गौवंश की देखभाल, चारे और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इस अवसर पर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में गोवर्धन पूजा का विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। यह पर्व प्रकृति, गौवंश और भगवान श्रीकृष्ण के प्रति आस्था एवं कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा और संरक्षण भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गौवंश की रक्षा और सेवा के लिए आगे आना चाहिए। विधायक ने कहा कि गौ सेवा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इस दौरान आश्रम से जुड़े लोगों ने विधायक का स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी गौ सेवा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए और गौवंश के संरक्षण का संकल्प लिया।

उड़ान भरने से ठीक पहले एयर इंडिया के विमान में हाईजैक अलर्ट



संवाददाता

कोलकाता। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब उड़ान भरने से ठीक पहले एयर इंडिया के एक विमान से हाईजैक (विमान अपहरण) का अलर्ट जारी किया गया। यह घटना कोलकाता से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 772 में बुधवार सुबह हुई। सूत्रों के अनुसार, विमान के उड़ान भरने से ठीक पहले पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को हाईजैक का संदेश भेजा। यह अलर्ट मिलते ही हवाई अड्डा प्राधिकरण और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गईं। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विमान को फौरन आइसोलेशन बे (सुरक्षित क्षेत्र) में ले जाया गया। सुरक्षाबलों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरे विमान को घेर लिया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद विमान की सघन तलाशी शुरू की गई।

भारत ने कृषि उत्पादन के तोड़े हैं कई रिकॉर्ड : शिवराज सिंह चौहान



संवाददाता

भोपाल। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन के कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। अभी चावल के उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर हम दुनिया में नंबर-1 हो गए हैं। भारत प्याज का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश इस समय बन गया है। आज देश में रिकॉर्ड उत्पादन 377 मीट्रिक टन अनाज और 378 मीट्रिक टन फल और सब्जियों का हो रहा है। केंद्रीय मंत्री चौहान बुधवार को भोपाल से एक टीवी कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर उक्त वीडियो साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं और चावल अब केवल हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं है, आज हम दुनिया में निर्यात करने का काम कर रहे हैं। हम भारत के 140 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और उन्हें पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराएंगे। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि माँ और भगवान एक समान होते हैं। लेकिन मैं माँ और भगवान के साथ किसान को भी बराबरी का दर्जा देता हूँ। अन्नदाता किसान जो जीवनदाता भी है, उनकी आय बढ़ाना, आजीविका को बेहतर करना, यह हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने तय किया था कि किसानों की अलग पहचान बनेगी। आज 11 करोड़ से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। अब तक हमारे वैज्ञानिक केवल लैब में अनुसंधान करते थे, लेकिन विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान हमने लैब को लैंड से जोड़ने का काम किया है। हमने यह फैसला भी किया है कि अब जितनी भी रिसर्च होगी, वह किसान की जरूरत के हिसाब से होगी। चौहान ने बताया कि किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए 'किसान क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं।

छठ महापर्व को लेकर उन्नाव पुलिस अलर्ट, गंगा घाट का किया निरीक्षण

लालखेड़ा घाट पर सुरक्षा और सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, गोताखोरों से कराई गई पानी की गहराई की जांच

संवाददाता

उन्नाव, उत्तर प्रदेश। आगामी छठ महापर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए उन्नाव पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी बीघापुर प्रदीप कुमार ने थाना बारासगवर क्षेत्र के ग्राम लालखेड़ा स्थित गंगा घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की संभावित भीड़, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई और आपातकालीन इंतजामों का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान गोताखोरों की मदद से घाट पर पानी की गहराई की जांच कराई गई। जांच में पानी अधिक गहरा नहीं पाया गया। इसके बावजूद किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए घाट की समुचित साफ-सफाई कराने और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी ने घाट पर नावों और गोताखोरों की उपलब्धता का भी निरीक्षण किया, ताकि किसी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तत्काल सहायता मिल सके। पुलिस प्रशासन का कहना है कि छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन और शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।



डीएम गौरांग राठी ने PHC टहरौली का किया औचक निरीक्षण, दवाओं के स्टॉक का किया सत्यापन

- हर महीने 600 ओपीडी और 30 प्रसव की जानकारी ली, मातृत्व एवं नवजात शिशु देखभाल यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश



देवेश प्रताप सिंह राठौर

झांसी, उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी गौरांग राठी ने मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिशिर पुरी के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) टहरौली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, प्रसव सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता, साफ-सफाई और अन्य चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्साधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिमाह लगभग 600 मरीज ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचते हैं। वहीं, यहां प्रतिमाह करीब 30 सामान्य प्रसव कराए जा रहे हैं। प्रसव संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के बाद जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र में मातृत्व एवं नवजात शिशु देखभाल यूनिट (मेटरनिटी न्यू बॉर्न केयर यूनिट) स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। भवन और परिसर के निरीक्षण के दौरान पुताई तथा साफ-सफाई की व्यवस्था में सुधार की जरूरत सामने आई। इस पर डीएम ने उप जिलाधिकारी टहरौली और खंड विकास अधिकारी गुरसराय को निर्देश दिया कि रोगी कल्याण समिति के खाते में दान के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र के संभ्रांत लोगों को प्रेरित करें। प्राप्त राशि का उपयोग स्वास्थ्य केंद्र की पुताई और साफ-सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने में किया जाए।

जिलाधिकारी ने औषधि वितरण केंद्र का भी निरीक्षण किया और स्टॉक रजिस्टर में दर्ज दवाओं की उपलब्धता का रैंडम सत्यापन किया। इस दौरान सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन के स्टॉक का रजिस्टर में दर्ज मात्रा से मिलान किया गया, जो सही पाया गया। उन्होंने दवाओं के स्टॉक रजिस्टर को नियमित रूप से अपडेट रखने और व्यवस्थित तरीके से संधारित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में एक महत्वपूर्ण मुद्दा सर्पदंश के मरीजों के उपचार को लेकर भी सामने आया। प्रभारी चिकित्साधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पर एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है, लेकिन सांप के काटने के मरीज उपचार के लिए यहां आने के बजाय जिला मुख्यालय पहुंच जाते हैं। इस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिया कि अपने अधीनस्थों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं, ताकि सर्पदंश से प्रभावित मरीजों को समय पर स्थानीय स्तर पर उपचार मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके।

जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि आमजन को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार किया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी गुरसराय डॉ. रविशंकर, उप जिलाधिकारी टहरौली आशीष कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. के.एल. पाल, डॉ. ओ.पी. राजपूत सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभर रहा मप्र : मुख्यमंत्री डॉ. यादव



संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थानों को तीर्थ स्थान बनाकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार की शाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय गोवर्धन पूजा उत्सव को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उत्तरप्रदेश सहित मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली के जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आयोजकों ने स्मृति चिन्ह, पगड़ी और गजमाला पहना कर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में गौमाता के संरक्षण के लिए कांजी हाऊस के स्थान पर 10 हजार गायों की देखभाल के लिये हाईटेक गौशालाएं प्रारंभ की जा रही हैं। राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गौपालन पर पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वृहद स्तर पर गोवर्धन पूजा के कार्यकम हुए हैं। समाज और सरकार ने मिलकर प्रकृति के पूजन के इस त्यौहार को उत्साह के साथ मनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण लोकतंत्र के नायक थे। उन्होंने जीवन में कभी सत्ताधीश बनने का कार्य नहीं किया। उनका जीवन धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अन्याय के विरूद्ध सत्य की लड़ाई लड़ते हुए वे विजयी हुए। उन्होंने पूरे जीवन में साहस और मुस्कराकर जीने का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया।

मालिक, प्रकाशक व मुद्रक- सुनील कुमार तिवारी द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट नं. ०४, ग्राउंड फ्लोर, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, ऑफ आरे रोड, नियर प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गेट नं ०२, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई-४०००६३ से मुद्रित व ६१७, बिल्डिंग नं. १४ नियर शिव शक्ति बिल्डिंग, गोलीबार रोड, सान्ताक्रूज (पूर्व), मुंबई-४०००५५ से प्रकाशित। **संपादक सुनील कुमार तिवारी,** RNI. NO. MAHMUL/2017/74054, **संपादकीय कार्यालयः ब्रह्मदीन शर्मा चाल, जवाहर नगर, साईबाबा रोड, खार (पूर्व) मुंबई - 400051, Mob. 8898271111**